संख्याः 501/XIX/खाद्य(रबी खरीद)/2005–06

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तरांचल देहरादून
2. जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर/हरिद्वार/पौडी/
देहरादून/नैनीताल/चम्पावत।
3. संभागीय खाद्य नियंत्रक,
कुमायूँ/गढवाल सम्भाग।
हल्द्वानी/देहरादून।
4. निदेशक,
मण्डी परिषद,
उत्तरांचल देहरादून।
5. अपर निबन्धक,
उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

देहरादून दिनॉक 31 मार्च, 2005

विषयः– रबी कय विपणन वर्ष 2005–06 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ कय की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रबी खरीद वर्ष 2005–06 में राज्य के कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केवल उत्तरांचल राज्य में उत्पादित गेहूँ का ही कय निम्नांकित अनुदेशो के अनुसार किया जायेगाः–

1. गेहूँ का मूल्य

भारत सरकार के पत्रांक 160(1)/2004–पी0वाई0–1, दिनॉक 07–12–2004 द्वारा रबी विपणन सत्र 2005–06 के लिए अच्छे औसत किस्म के गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू 640.00 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है, जो निम्नवत् है :–

फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुन्तल
गेहूँ	640.00

2. गेहूँ की गुण विनिर्दिष्टयॉ

उपभोक्ता मामलें, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 7–1/2005–एस0एण्ड आई, दिनॉक 11 मार्च, 2005 के अनुसार निर्धारित गुण निर्दिष्टियों के अनुसार गेहूँ कय किया जायेगा जो परिशिष्ट–6 पर संलग्न है ।

3. कय एजेन्सियॉ एवं खरीद का लक्ष्य

(क) शासन द्वारा रबी कय योजना वर्ष 2005–06 के अन्तर्गत गेहूँ कय करने हेतु निम्नलिखित कय एजेन्सियॉ नामित की जाती है। कय एजेन्सिसों तथा उनके द्वारा खोले जाने वाले कय केन्द्र तथाएजेन्सियों के लिए निर्धारित कार्यकारी लक्ष्य निम्न प्रकार है :–

क0सं0	कय एजेन्सी का नाम	केन्द्रो की संख्या	लक्ष्य मी0 टन में
1.	खाद्य विभाग (विपणन शाखा)	29	25,000
2.	भारतीय खाद्य निगम	30	30,000
3.	उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ	165	1,40,000
4.	उत्तरांचल ऐग्रो इकाई	05	5,000
	योगः–	229	2,00,000

गेहूँ का कय विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा जिसके अन्तर्गत 85.00 हजार मी0टन का संग्रहण स्टेट पूल में तथा शेष कय किया जाने वाला गेहूँ केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जायेगा।

(ख) उक्त के अतिरिक्त यदि कोई अन्य संस्थायें गेहूँ क्रय का कार्य करने में रूचि दिखाती है और आवेदन करती है तो गुण दोष के आधार पर उन संस्थाओं को गेहूँ क्रय कार्य करने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा क्रय केन्द्र पर लाये गये प्रत्येक कृषक का गेहूँ खरीदा जायेगा, चाहे वह सहकारी समिति का सदस्य हो अथवा न हो। उनके द्वारा ऐसी भी शर्त नहीं लगायी जायेगी कि पहले किसान द्वारा उनके बकाया का भुगतान किया जाये, तभी उनका गेहूँ खरीदा जायेगा।

4. समय सारिणी

रबी विपणन वर्ष 2005–2006 में गेहूँ क्रय हेतु आवश्यक व्यवस्था **परिशिष्ट–1** पर संलग्न समय सारिणी के अनुसार विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। तद्नुसार सभी संबंधित यथासमय वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

5. जिला खरीद अधिकारी का नामांकन

उत्तरांचल में रबी विपणन सत्र 2005–2006 में गेहूँ खरीद के कार्य को प्रभावी एवं सुचारू ढंग से सम्पादित कराने हेतु जिलाधिकारी द्वारा एक "जिला खरीद अधिकारी" नामित किया जायेगा। यह अधिकारी अपर जिला अधिकारी के समकक्ष स्तर का होगा, जिसे गेहूँ खरीद के कार्य को प्रभावी रूप से संचालित करने का दायित्व होगा एवं जो विभिन्न क्रय एजेंसियों एवं भण्डारण एजेंसी के बीच समन्वय भी स्थापित करेगा।

6. क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं स्थापना

जनपद में गेहूँ के उत्पादन एवं विपणन अतिरेक (Marketable Surplus) की परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में गेहूँ के आवक का आंकलन स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा संभागीय खाद्य नियंत्रक के सहयोग से किया जायेगा। किसानों के विपणन योग्य सरप्लस की मात्रा को ध्यान में रखते हुए ग्रामों के सम्बद्धीकरण के आधार पर क्रय केन्द्रों का निर्धारण किया जायेगा। क्रय केन्द्रों से सम्बन्धित ग्रामों की किसानवार सूचियाँ सम्बन्धित संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी एवं क्रय संस्थायें यह सुनिश्चित करेगी कि गेहूँ खरीद का कार्य किसी भी प्रकार प्रभावित न हो। क्रय केन्द्र खोलने में यह विशेषकर ध्यान देने योग्य है, कि एक ही स्थान पर आवश्यकता से अधिक संख्या में क्रय केन्द्र न खोले जाये। ऐसी भी स्थिति न उत्पन्न हो कि किसानों को अपने खेतों से बहुत दूर गेहूँ ले जाना पडे क्योंकि इससे "डिस्ट्रेस सेल" के अवसर उपलब्ध होंगे। अतः क्रय केन्द्रों के स्थान, निर्धारित करते समय यह अवश्य ध्यान में रखा जाये कि 10 कि0मी0 की परिधि में कम से कम एक क्रय केन्द्र अवश्य खोला जाये। वर्तमान खरीद वर्ष 2005–2006 में गेहूँ की अच्छी फसल को दृष्टिगत रखते हुए जिले में खरीद कार्य हेतु नामित क्रय एजेंसियों के अधिकारी अपने क्रय केन्द्रों की सूची जिला अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार एवं शासन की नीति के अन्तर्गत गेहूँ क्रय केन्द्रों के स्थान तय करेंगे। सभी क्रय एजेंसियां जिला अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर क्रय केन्द्र खोलना सुनिश्चित करेगी। क्रय केन्द्र निर्धारित स्थान पर विलम्बतम 10 अप्रैल, 2005 तक निश्चित रूप से खुल जाय तथा खरीद हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें भी सुनिश्चित कर ली जाये।

7. क्रय एजेंसियों को बोरे उपलब्ध कराना

(1) भारतीय खाद्य निगम को छोडकर अन्य क्रय संस्थाओं की गेहूँ खरीद के लिए बोरों की व्यवस्था खाद्य विभाग द्वारा की जायेगी। वर्ष 2005–2006 में केवल 50 कि0ग्रा0 भर्ती वाले एस0बी0टी0 बोरे ही प्रयुक्त किये जायेंगे। गेहूँ खरीद के दौरान प्रत्येक क्रय केन्द्र पर न्यूनतम एक गांठ बोरों की हर समय उपलब्धता बनी रहने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए लगभग 40.00 लाख बोरों की आवश्यकता होगी। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने क्रय केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार बोरों की व्यवस्था स्वयं की जायेगी।

(2) उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ, उत्तरांचल ऐग्रो इकाई अथवा शासन द्वारा नामित अन्य क्रय संस्थाओं को बोरों की आपूर्ति, संभागीय खाद्य नियंत्रक, द्वारा संबंधित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय अधिकारी की लिखित मांग पर प्रारम्भ में अप्रैल माह की आवश्यकता के अनुसार उधार आधार पर की जायगी तथा अनुवर्ती मांग पर बोरे तभी दिये जायेंगे, जब पूर्व में उधार आधार पर दिये गये बोरों के मूल्य का भुगतान क्रय एजेंसी द्वारा कर दिया जाय। संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा उपलब्धतानुसार गोदामों से आवंटित बोरों के उठान एवं आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्रों पर सुलभ कराने का दायित्व संबंधित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय समन्वयक अधिकारी का होगा।

8. गेहूँ खरीद हेतु धन की व्यवस्था एवं कृषकों को भुगतान

(1) भारतीय खाद्य निगम द्वारा जितनी मात्रा में गेहूँ की खरीद मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय एजेन्सी के रूप में कार्य करते हुए अपने द्वारा संचालित कय केन्द्रों पर की जायेगी, उस मात्रा के लिए किसानों को भुगतान हेतु धन की व्यवस्था उनके द्वारा स्वयं की जायेगी।

(2) खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा संचालित कय केन्द्रों में कय किए जाने वाले गेहूँ के भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृत कराई जा रही है कैश केडिट लिमिट से अग्रिम के रूप में धन उपलब्ध कराया जायेगा। यह धन रिवाल्विंग फण्ड के रूप में रहेगा।

(3) उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ (U.C.M.F) के द्वारा अपने क्रय केन्द्रों पर गेहूँ क्रय के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से रिवाल्विंग फण्ड से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। क्रय किए गए गेहूँ को स्टेट पूल अथवा केन्द्रीय पूल में सम्प्रदान कर नियमानुसार बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) यदि उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ (U.C.M.F) द्वारा कैश केडिट लिमिट से धन की मांग की जाती है तो उनके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज अदा करना होगा। ब्याज की शर्तें वही होंगी जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

(5) राज्य सरकार की क्रय एजेन्सियों (खाद्य विभाग एवं उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ तथा उत्तरांचल ऐग्रो इकाई) द्वारा किसानों से क्रय किए गए गेहूँ की डिलीवरी स्टेट पूल/केन्द्रीय पूल में शीघ्रता से इस प्रकार की जाएगी कि Flow of Funds लगातार बना रहें।

(2) कृषकों से क्रय किये गये गेहूँ के मूल्य का भुगतान करने में तत्परता सुनिश्चित की जायेगी ताकि किसी प्रकार के विलम्ब से उन्हें असंतोष न रहें। गेहूँ की खरीद सामान्यतः दृष्टि परीक्षण के आधार पर की जाती है। तदनुसार गुण निर्दिष्टियों के अनुरूप गेहूँ खरीद करके, संबंधित अभिलेखों में स्पष्ट प्रविष्टि के उपरान्त कृषकों को, केन्द्र प्रभारी द्वारा गेहूँ के मूल्य का भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा। इस कार्य के लिए बैंकों में " Wheat Purchase Account" के नाम से चालू खाता खोलकर क्रय एजेंसियॉं अपने नियमों के अनुसार काश्तकारों को भुगतान सुनिश्चित करेगी। उत्पादको/कृषकों को गेहूँ के मूल्य के रूप में मिलने वाली धनराशि की सुरक्षा की दृष्टि से रूपये 10,000/–(रू0 दस हजार मात्र) तक की धनराशि के चैक आर्डर अंकन तथा रूपये 10,000/– (रू0 दस हजार मात्र) या उससे अधिक के चैक "क्रास्ड" अंकन कर निर्गत किये जायेगे। यदि कोई छोटा काश्तकार जिसको कुल देय धनराशि रूपये 5,000/–(रू0 पांच हजार मात्र) से अनधिक हो, और वह लिखित रूप से यह अनुरोध करें कि उसे आर्डर चैक न देकर "बेयरर चैक" निर्गत किया जाय तो उसे बेयरर चैक दिया जा सकता है, किन्तु चैक निर्गत करने से पूर्व उसे इस तथ्य की जानकारी दी जाए कि बेयरर चैक से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसका भुगतान ले लिये जाने पर, उसकी जिम्मेदारी चैक प्राप्तकर्ता की होगी। सभी क्रय एजेंसियों द्वारा भुगतान से संबंधित उपरोक्त सामान्य अनुदेशों का कडाई से पालन किया जायेगा।

9. क्रय केन्द्रों पर सुविधायें

(1) क्रय एजेंसियों द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर कृषकों को सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्व उत्तरांचल राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद का है। तदनुसार मण्डी समितियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में खोले गये क्रय केन्द्रों पर कृषकों की सुख सुविधा के निमित्त निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जाये:–

(क) क्रय केन्द्रों पर प्रदर्शनार्थ सूचनापट।

(ख) किसानों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था हेतु बाल्टी, लोटा गिलास मिट्टी के मटके एवं वाटरमैन आदि।

(ग) बैलगाडी, ट्रक, ट्राली आदि की पार्किंग के लिए पार्किंग स्थल एवं जानवरों को पानी पिलाने के लिए नॉद एवं पानी की व्यवस्था।

(घ) कृषकों को बैठने कि लिये तख्त, दरी एवं साया के लिए शैड/शामियाना आदि।

(च) गेहूँ की सफाई के लिए पर्याप्त संख्या में दो जाली वाले उपयुक्त किस्म के छलने एवं पंखे।

(छ) असामयिक वर्षा से कृषकों द्वारा लाये गये गेहूँ की सुरक्षा हेतु आवश्यक संख्या में तिरपाल/पॉलीथीन शीट आदि।

(ज) गेहूँ से भरे बोरों की सिलाई हेतु स्टिचिंग मशीन की व्यवस्था।

(2) यदि मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल अथवा उसे बाहर स्थित क्रय केन्द्रों पर मण्डी समितियों द्वारा उपरोक्तानुसार सुख सुविधा की व्यवस्था नहीं की जाती है तो मण्डी समिति की ओर से यह व्यवस्था क्रय एजेंसी द्वारा स्वयं सुनिश्चित की जायेगी। जिसमें होने वाले व्यय का समायोजन मण्डी शुल्क से निम्नानुसार कर लिया जायेगा:-

क्र0सं0	क्रय केन्द्र पर खरीद मात्रा	अनुमन्य व्यय सीमायें
1	सीजन में 250 मी0टन तक खरीद वाले क्रय केन्द्र	रूपये 5,000/- प्रति केन्द्र
2	सीजन में 251 से 600 मी0टन खरीद वाले क्रय केन्द्र	रूपये 10,000/- प्रति केन्द्र
3	सीजन में 600 मी0टन से अधिक खरीद वाले क्रय केन्द्र	रूपये 15,000/- प्रति केन्द्र

कृषकों को शासनादेशानुसार सुविधा सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरांचल मण्डी निदेशक द्वारा इस संबंध में अपने विभाग की ओर से मण्डी समितियों को पृथक से भी आदेश निर्गत किये जायेंगे।

10. हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का भुगतान

(1) क्रय केन्द्रों पर काश्तकारों द्वारा लाये गये गेहूँ की बोरों में भराई, स्टैन्सिलिंग, सिलाई, तुलाई एवं ट्रकों में लोडिंग आदि कार्यों के लिए हैण्डलिंग ठेकेदारो की नियुक्ति का कार्य संबंधित क्रय एजेंसी द्वारा किया जायेगा। ठेकेदारों की नियुक्ति का कार्य नियमानुसार शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाये ताकि खरीद में कठिनाई न हो।

(2) जहाँ तक हैण्डलिंग ठेकेदारों के लिये पारिश्रमिक दरों का संबंध है, इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन ने निर्णय लिया है कि हैण्डलिंग ठेकेदारों को उनकी सेवाओं के लिए स्थानीय प्रचलित दर पर अथवा निम्नलिखित उच्चतम दरों, जो भी कम हो, के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाये:-

क्र0सं0	मद	प्रति कुन्टल अधिकतम दर (रूपये में)	
		95 कि0ग्रा0	50 कि0ग्रा0
1.	खाद्यान्नों की बोरो मे मार्क लगाकर भराई, तुलाई, बॉट तथा माप, सुतली का प्रबन्ध, 16 टॉको की सिलाई	2.00	3.30
2.	भरे बोरों के स्थानीय चट्टे लगाना	0.60	1.00
3.	स्थानीय चट्टे से उठाकर ट्रक पर लदायी	0.60	1.00
4.	भरे बोरों को स्थानीय चट्टे से हटाकर गोदाम/ अहाते में 16 छल्ली तक पक्के चट्टे लगाना तथा पक्के चट्टे से बोरों को उतरवाकर 10 प्रतिशत तौल के उपरान्त ट्रक पर लदायी	0.70	1.20
	योग:-	3.90	6.50

(3) शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि प्रायः हैण्डलिंग ठेकेदार कम दरों पर ठेके लेकर किसानों से अनुचित कटौतियाँ करते हैं, जिससे किसानों का शोषण होता है। ठेकेदारों की इस अनुचित प्रवृत्ति को रोकने के उददेश्य से हैण्डलिंग ठेकेदारों को 95 कि0ग्रा0 तथा 50 कि0ग्रा0 भर्ती के बारों की उपरोक्तानुसार हैण्डलिंग के लिये क्रमशः रूपया 2.00 एवं रूपया 3.30 प्रति कुन्टल से कम दर पर ठेका बिल्कुल न दिया जाये। ऐसे व्यक्तियों

जिनका कार्य खराब पाया जाये और उनकी शिकायतें प्राप्त हुई हो तो गुण–दोष के आधार पर भविष्य में उन्हें ठेकेदार न नियुक्त किया जाये।

(4) हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति, जमानत की धनराशि जमा कराने तथा अनुबंध पत्र भरने की कार्यवाही पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–पी0–813/29–खा0–5–5(5)/89 दिनांक 07 अप्रैल, 1989 के अनुसार की जायेगी। (परिशिष्ट–2)

11. क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये गेहूँ के सम्प्रदान एवं बोरों की व्यवस्था हेतु परिवहन व्यय की दरों का निर्धारण तथा परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति

(1) रबी खरीद वर्ष 2005–2006 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ की खरीद विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत की जायेगी जिसके तहत 85 हजार मी0टन गेहूँ का सम्प्रदान स्टेट पूल में तथा क्रय किये जाने वाला अतिरिक्त गेहूँ केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जायेगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्न के संचरण हेतु परिवहन व्यवस्था समय से की जानी अपेक्षित है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन दरों में एकरूपता बनाये रखने के लिए ट्रान्सपोर्ट ठेकेदारों को भुगतान के लिए दरों के निर्धारण का दायित्व जिलाधिकारी का होगा। दरों का निर्धारण करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी,भारतीय खाद्य निगम,लोक निमार्ण विभाग,सिचाई विभाग तथा ट्रान्सपोर्ट यूनियनों से प्रचलित दरें ज्ञात की जायेगी तथा डीजल की दरों में वृद्धि आदि को ध्यान में रखकर खाद्यान्न एंव बोरों के परिवहन हेतु दरों का निर्धारण तथा ट्रकों की व्यवस्था के लिए शासनादेश सं0–पी0–372/29–गेंहू–1–5(12)/79दिनांक 09 अप्रैल, 1979(परिशिष्ट–3)के प्रस्तर–2 मे उल्लिखित सांकेतिक दरों की भॉति प्रचलित बाजार दरों को ध्यान में रखकर की जायेगी।

(2) ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों को टेण्डर के आधार पर नियुक्त करने में वही मापदण्ड एवं प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो रबी खरीद वर्ष 2004–05 एवं पूर्ववर्ती वर्षो में अपनायी जाती रही है। अच्छी साख एवं ईमानदारी की साख वाले व्यक्तियों को ठेकेदार नियुक्त किया जाये तथा यथासम्भव खाद्यान्न व्यापारियों को ठेकेदार न नियुक्त किया जाये। यदि अपरिहार्य एवं विशेष परिस्थितियो में खाद्यान्न व्यापारियों को नियुक्त करना ही पडे, तो ऐसे व्यक्तियों को ठेकेदार नियुक्त किया जाये, जिनके विरूद्ध कोई शिकायत न हो। ठेकेदारों की नियुक्ति में पुराने, अनुभवी तथा ऐसे व्यक्तियों को वरीयता दी जाय, जिनके पास अपने ट्रक हों। इस बात को सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित जिलाधिकारी एवं संबंधित क्रय एजेंसी का होगा कि ठेकेदार गेहूँ खरीद में बिचौलियों का कार्य न करने पाये।

(3) नियुक्त ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों के हस्ताक्षर के नमूने एवं उनके द्वारा परिवहन कार्य में लगाये गये ट्रकों के रजिस्ट्रेशन नम्बर सभी संबंधित क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जायेंगे तथा ठेकेदारों को आदेश दिये जाये कि जब भी वह ट्रकों को राजकीय खाद्यान्न के परिवहन हेतु भेजे तो ट्रक ड्राईवर के हस्ताक्षर को भी अपने पैड पर सत्यापित करके भेजे। ताकि केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित कर सके कि उक्त ट्रक परिवहन ठेकेदार के आदेश से ही भेजा गया है।

(4) प्रत्येक क्रय केन्द्र पर प्रतिदिन की खरीद के अनुपात में ट्रकों की आवश्यकता का आंकलन कर अनुबंध पत्र में यह शर्त अवश्य जोडी जाये कि न्यूनतम ट्रकों की उपलब्धता नियुक्त ठेकेदार पास हमेशा रहेगी। यह भी ध्यान रखा जाये कि ठेकेदार से अनुबंध पत्र भराने के बाद ही कार्य कराना प्रारम्भ किया जाये।

(5) ट्रान्सपोर्ट ठेकेदार से रूपये 15,000/– की नकद जमानत एवं क्रय केन्द्र पर (जिस वर्ष अधिकतम खरीद हुई थी के आधार पर) अधिकतम 10 दिन की खरीद मात्रा के मूल्य की दस प्रतिशत धनराशि के बराबर फैडिलिटि गारन्टी बान्ड राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में लिया जाय। यह भी स्पष्ट करना है कि अनुबन्ध तथा जमानत पर स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प एक्ट की अनुसूची में निर्धारित दर के अनुसार लगेगा, जो ट्रांसप्रोर्ट ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि जिन केन्द्रों पर खरीद की मात्रा कम होने के कारण परिवहन कार्य को सम्पन्न

करने में कठिनाई हो रही हो तो वहाँ संबंधित जिलाधिकारी/संभागीय खाद्य नियंत्रक अपने विवेक से अन्य प्रतिबन्धों को यथावत रखते हुए जमानत की धनराशि न्यूनतम रूपये 5,000/–तक रख सकते है, परन्तु जमानत कम करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्यवाही में शासन को कोई हानि न हो। यदि ट्रांसपोर्ट ठेकेदार से गेहूँ के संचरण में कोई क्षति होती है तो उससे इस क्षति के मूल्य के डेढ गुना मूल्य की धनराशि के बराबर क्षतिपूर्ति करायी जायेगी। इस शर्त को भी अनुबन्ध पत्र में रखा जायेगा। ऐसे सभी मामलों का विवरण संबंधित कय एजेंसी के वित्त नियंत्रक एवं विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा।

(6) उपर्युक्त विवरण केअनुसार परिवहन दरों का निर्धारण एवं ट्रान्सपोर्ट ठेकेदारों की नियुक्ति तथा उनके अनुबन्ध भराने आदि की कार्यवाही निर्धारित समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित कर ली जाये।

12. कय केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले कॉटा–बॉट का सत्यापन

कय केन्द्रों पर प्रयोग के लिये रखे गये बॉट तथा माप का सत्यापन समय समय पर नियमानुसार नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा किया जायेगा। संबंधित विधिक बाट माप निरीक्षक 10 अप्रैल से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि गेहूँ कय योजना 2005–06 में स्थापित होने वाले सभी कय केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले कॉटा–बॉट का सत्यापन/मानकीकरण/मुद्रांकन कर दिया जाए। साथ ही समस्त कय एजेंसियाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि कय केन्द्रों पर सही बाट तथा कॉटे का प्रयोग हो। किसी भी दशा में ईट, पत्थर अथवा इस प्रकार के मानक बॉटों से भिन्न किसी भी वस्तु का प्रयोग बॉट के रूप में तौल हेतु न किया जाय। किसी भी दशा में घटतौली तथा बढतौली की शिकायत न होने पाये।

13. कय केन्द्रों हेतु भूमि का किराया

यदि किसी कय एजेंसी को कय हेतु भूमि किराये पर लेनी पडती है तो किराया भुगतान उसके द्वारा अनुमन्य प्रासंगिक व्यय से किया जायेगा, इसके लिए शासन से कोई अतिरिक्त धनराशि अनुमन्य नहीं की जायेगी। भूमि का किराया एकरूपता तथा मितव्ययिता की दृष्टि से जिलाधिकारी द्वारा प्रति वर्ग मी0 क्षेत्रफल के लिए निर्धारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की दर अधिकतम होगी।

14. कय अवधि

10 अप्रैल, 2004 से मण्डी में गेहूँ की आवक होने के साथ ही समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ कय का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा और यह कय अवधि 30 जून 2004 तक रहेगी। मितव्ययता की दृष्टि से और कम आवक के कारण यदि कोई कय केन्द्र बन्द करने की आवश्यकता होती है तो जिलाधिकारी ऐसे कय केन्द्रों को बन्द करने का निर्णय स्वविवेकानुसार ले सकते है। सामान्यतः कय केन्द्र प्रातः 07 बजे से सांयकाल 07 बजे तक खुले रहेंगे। आवश्यकता पडने पर कय समय की वृद्वि की जा सकती हैं। रविवार तथा अन्य अवकाश के दिनों में भी कय केन्द्र नियमित रूप से खुले रहेगें।

15. स्टेट पूल योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये गेहूँ की संचरण व्यवस्था

गढवाल संभाग में गेहूँ की खरीद अपेक्षाकृत कुमायूँ संभाग के सापेक्ष नगण्य होने एवं गढ़वाल संभाग की विभिन्न योजनाओं में गेहूँ की केन्द्रवार आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कुमायूँ संभाग/गढवाल संभाग में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ तथा उत्तरांचल ऐग्रो इकाई द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये गेहूँ का संचरण प्रोग्राम **परिशिष्ट–7** के अनुसार कुमायूँ संभाग/गढ़वाल संभाग के गेहूँ कय केन्द्रो से सीधे स्टेटपूल गोदामों हेतु किया जायेगा,ताकि विकेन्द्रीकृत योजनान्तर्गत कुमायूँ संभाग के साथ–साथ गढ़वाल संभाग में भी आवंटन के अनुरूप गेहूँ की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। केन्द्रीय भण्डारण निगम, श्रीनगर

हेतु गेहूँ की आपूर्ति चावल की भाँति ऋषिकेश केन्द्र से की जायेगी। संभागीय खाद्य नियंत्रक अपने–अपने संभाग में भण्डारण ऐजेन्सियों की आरक्षित संग्रहण क्षमता के पूर्ण उपयोग के साथ–साथ अन्तर–संभाग (inter-regional) गेहूँ का ऐसा संचरण/भण्डारण करायेंगे कि आन्तरिक गोदामों को गेहूँ की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

16. क्रय केन्द्रों पर अभिलेखों का रख–रखाव

प्रत्येक क्रय एजेंसी द्वारा क्रय केन्द्रों पर अनिवार्य रूप से निम्नलिखित अभिलेख रखे जायेंगे।

1. आवक–क्रम एवं टोकन रजिस्टर
2. पर्ची काश्तकार
3. क्रय पंजिका
4. स्टॉक रजिस्टर
5. रिजेक्शन रजिस्टर
6. निरीक्षण पंजिका
7. बैंक लेखा पंजी/चैक बुक/निर्गत चैकों की विवरण पंजिका
8. मूवमेन्ट चालान बुक
9. शासनादेश की पत्रावली
10. खरीद एवं सम्प्रदान के दैनिक विवरण पत्रों की पत्रावली
11. शिकायत पुस्तिका

माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर रिजेक्शन रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका तथा शिकायत पंजिका दिखाई जायेगी।

17. खरीद प्रकिया

(1) मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ सीधे किसानों से क्रय किया जायेगा। किसी बिचौलिये/व्यापारी द्वारा लाया गया गेहूँ किसी भी दशा में क्रय नहीं किया जायेगा। यह पूर्व में भी स्पष्ट किया जा चुका है और पुनः स्पष्ट किया जा रहा है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों पर गेहूँ लाने वाले प्रत्येक किसान का गेहूँ खरीदा जायेगा चाहे वह उस संस्था/समिति का सदस्य हो अथवा नहीं । सहकारी संस्थाओं द्वारा ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जायेगी कि किसान पहले उनके बकाया का भुगतान करें, तभी उनका गेहूँ खरीदा जायेगा।

(2) राज्य के सूचना विभाग एवं मण्डी परिषद द्वारा क्रय योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा। संबंधित मण्डी समितियों भी इस आशय का प्रचार करेगीं कि किसान अपना गेहूँ साफ कर एवं सुखा कर क्रय केन्द्र पर विक्रय हेतु लाये, ताकि उन्हें निर्धारित समर्थन मूल्य का पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त हो सके। यदि कृषक द्वारा साफ गेहूँ नहीं लाया जाता है तो उसे क्रय करने से पूर्व दो जाली वाले छलने से भली प्रकार अनिवार्यतः साफ कराकर ही क्रय किया जायेगा। आवश्यकतानुसार गेहूँ की सफाई हेतु क्रय केन्द्रों पर पंखों की भी व्यवस्था की जाये। यदि किसी कृषक द्वारा स्वंय गेहूँ साफ न करके, गेहूँ की सफाई का कार्य हैण्डलिंग ठेकेदार के माध्यम से कराया जाता है तो काश्तकार से मण्डी समिति द्वारा इस कार्य हेतु निर्धारित दर से सफाई का मूल्य उसके भुगतान के समायोजन द्वारा लिया जायेगा। किसी सी दशा में क्रय केन्द्र पर नकद धनराशि नहीं ली जायेगी।

(3) कय केन्द्र पर निर्धारित गुण–निर्दिष्टयों का ही गेहूँ कय किया जायेगा। गुण–निर्दिष्टयों के अनुसार अच्छे औसत दर्जे के गेहूँ का एक नमूना सील कर कय केन्द्र में पारदर्शी जार में रखा जायेगा, जो कृषकों तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों एवं माननीय जन प्रतिनिधियों को प्रदर्शित कराया जायेगा। यह नमूना कय केन्द्र पर ऐसे स्थान पर रखा जायेगा ताकि आने वाले किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई दे। सैम्पल जार पर बडे अक्षरों में "प्रतिनिधि नमूना" लिखा होगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कय किये गये गेहूँ की गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी कयकर्ता एजेन्सी की होगी। स्टेट पूल डिपो/भारतीय खाद्य निगम डिपों पर सम्प्रदान के समय गेहूँ की गुणवत्ता में यदि कमी पाई जाती है तो उसके लिए संबंधित कयकर्ता कर्मचारी तथा कय एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा।

(4) सामान्यतः एक दिन में एक कॉटे में 1,000 बोरे अर्थात 500 कुन्तल से अधिक की तुलाई नही हो सकेगी। कय एजेन्सी के प्रभारी प्रत्येक केन्द्र में विपणन योग्य सरप्लस (Marketable surplus) के आधार पर कांटों की संख्या का निर्धारण कर लेगें। कांटों की संख्या निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जायगा कि इनको देखने के लिए स्टाफ पर्याप्त हो तथा कय अवधि अनावश्यक रूप से अधिक न हो जॉय।

(5) जैसे ही कय केन्द्र पर किसान अपने गेहूँ का नमूना लेकर आता है केन्द्र प्रभारी द्वारा उसकी जॉच की जायगी। केन्द्र प्रभारी के पास उपलब्ध ग्रामवार सूचियों में किसान का नाम तथा उसके पास उपलब्ध मात्रा देखकर उसका नाम पंजिका में अंकित कर लिया जायेगा और किसान को गेहूँ लाने के लिए एक तिथि दे दी जायेगी। निर्धारित तिथि को गेहूँ लाने पर किसान का गेहूँ कय कर लिया जायेगा। सूची में अंकित किसानों के विपणन योग्य सरप्लस से यदि वास्तविक मात्रा में कुछ विचलन है तो 10 प्रतिशत तक विचलन (धनात्मक/ऋणात्मक) स्वीकार कर लिया जायेगा। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाय कि किसानों को अनावश्यक रूप से कय केन्द्रों पर रूकना न पडें।

(6) गेहूँ की बोरों में भराई, सिलाई तथा सटैंलिसिंग के संबंध में निम्न व्यवस्था रहेगी: –

(क) बोरों में 50 किग्रा0 गेहूँ की स्टैण्डर्ड भराई की जायेगी।

(ख) बोरों की सिलाई मशीन अथवा 16 टांको से मजबूत सुतली से की जायेगी।

(ग) प्रत्येक बोरे पर भराई की तिथि, भरते समय का वजन, कय केन्द्रों का नाम एवं जनपद/कय एजेन्सी/कय केन्द्र का कोड नम्बर अंकित होगा।

कोड नं0 निम्न प्रकार होंगे : –

(अ)	कय एजेन्सी का नाम	कोड नम्बर
1.	खाद्य विभाग (विपणन शाखा)	01
2.	भारतीय खाद्य निगम	02
3.	उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ	03
4.	उत्तरांचल ऐग्रो इकाई	04

(ब)	जनपद का नाम	कोड नम्बर
1.	देहरादून	001
2.	पौड़ी	002
3.	हरिद्वार	003
4.	नैनीताल	004
5.	उधमसिंह नगर	005

कय केन्द्रों के कोड कय एजेन्सियों द्वारा निर्धारित कर जिलाधिकारी, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, भारतीय खाद्य निगम एवं शासन को दिनॉक 10 अप्रैल, 2004 से पूर्व सूचित किये जायेंगे।

(घ) बोरों की स्टैंसिलिंग पठनीय तथा चटख रंग से की जायेगी।

(च) स्टैंसिलिंग के निमित्त खाद्य विभाग (विपणन शाखा) द्वारा लाल रंग, भारतीय खाद्य निगम द्वारा हरा रंग तथा उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ द्वारा काला रंग एवं उत्तरांचल ऐग्रो इकाई द्वारा नीला रंग प्रयोग में लाया जायेगा।

उपरोक्तानुसार सिलाई एवं स्टैंसिलिंग व सफाई न करने पर कय एजेन्सियॉ ठेकेदार से यथास्थिति निम्न प्रकार कटौतियॉ करेंगी : –

कं0सं0	विवरण	कटौती की दर
1.	खराब सिलाई 16 टॉकों से कम	रू0 0.10 पैसे प्रति बोरा
2.	स्टैंसिलिंग न करना/खराब करना	रू0 0.15 पैसे प्रति बोरा
3.	गेहूँ में जीवित घुन पाया जाना (फ्यूमिगेशन चार्जेज)	रू0 0.50 पैसे प्रति बोरा

(6) यदि कय केन्द्र पर किसी कारण किसान का गेहूँ अस्वीकृत किया जाता है तो रिजेक्शन रजिस्टर में कृषक का नाम, उसका पूरा पता, लाये गये गेहूँ की मात्रा, अस्वीकृत किये गये गेहूँ की मात्रा तथा अस्वीकार किये जाने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण, अस्वीकार करने वाले अधिकारी का नाम अंकित किया जायेगा। इस कारण की सूचना कृषक को भी दी जायेगी। यह रिजेक्शन रजिस्टर मांग किये जाने पर संबंधित कृषक, माननीय जन प्रतिनिधिगण तथा निरीक्षकर्ता अधिकारियों को दिखाया जायेगा।

(7) कय केन्द्रों पर खरीदे गये तथा सम्प्रदान हेतु अवशेष गेहूँ की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संबंधित कय एजेन्सियों का होगा। सुरक्षा के लिए सभी वांछित उपाय कय एजेन्सी करेगी। इस पर होने वाला व्यय अनुमन्य प्रासंगिक व्यय से ही वहन किया जायेगा तथा शासन/भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस मद में अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

18. भारतीय खाद्य निगम को कय किये गये गेहूँ का सम्प्रदान

(1) गेहूँ का कय विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा जिसके अन्तर्गत 85.00 हजार मी0ट0 का सम्प्रदान/संग्रहण स्टेट पूल में तथा कय किया जाने वाला अतिरिक्त गेहूँ केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जायेगा।

(2) कय केन्द्र से स्टेट पूल डिपोज/भारतीय खाद्य निगम के डिपो तक गेहूँ की ढुलाई संबंधित कय एजेन्सियों द्वारा कराई जायेगी।

(3) जिला प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम द्वारा कय केन्द्रों को डिपो डिलीवरी बिन्दुओं से सम्बद्ध करने कि लिए मूवमेन्ट प्लान उपलब्ध कराया जायेगा। खरीदा गया गेहूँ कय केन्द्रों पर अनावश्यक रूप से जमा न हों, इसके लिये आवश्यक है कि गेहूँ का संचरण खरीद केन्द्रों द्वारा खरीद के दिन से ही प्रारम्भ किया जाये।

विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत गेहूँ के सम्प्रदान/संग्रह हेतु क्रय केन्द्रों को स्टेट पूल से संबद्ध करने हेतु संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा मूवमेन्ट प्लान तैयार किया जायेगा।

(4) भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर प्रत्येक क्रय एजेन्सी द्वारा अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया जायेगा तथा भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर जो ट्रक सांयकाल 5 बजे तक पहुँच जायेगा उनकी उतराई उसी दिन की जायेगी।

(5) भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर गेहूँ का लोडेड ट्रक पहुँचने पर ट्रक का विवरण गेट प्रवेश पंजिका में अंकित करके ड्राईवर को टोकन दिया जायेगा। जिसमें ट्रक के डिपो पर पहुँचने की तिथि तथा क्रम संख्या का उल्लेख होगा। भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर क्रम संख्या के अनुसार ही ट्रकों की अनलोडिंग की जायेगी।

(6) भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर गेहूँ की डिलीवरी ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर वे-ब्रिज की सुविधा उपलब्ध है ताकि शत प्रतिशत तौल सुनिश्चित हो सके, परन्तु जहाँ यह सुविधा न हो वहाँ गेहूँ के बोरों की 10 प्रतिशत तौल के आधार पर डिलीवरी लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) भारतीय खाद्य निगम/स्टेट पूल डिपोज द्वारा स्टाक के स्वीकृति के 24 घन्टे के अन्दर संबंधित क्रय एजेन्सी को गेहूँ का एक्नालेजमेंट दिया जायेगा तथा क्रय एजेन्सी द्वारा बिल प्रस्तुत करने के 72 घन्टे के अन्दर भुगतान कर लिया जायेगा। क्रय एजेन्सियों को यह दायित्व होगा कि वह भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज से अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिदिन एक्नालेजमेन्ट प्राप्त करेंगे।

19. <u>सम्प्रदान के समय गेहूँ की गुणवत्ता संबंधी विवाद का निराकरण।</u>

सम्प्रदान के समय गेहूँ की गुणवत्ता संबंधी विवादों के निराकरण के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जायेगी।

(1) विवाद की दशा में भारतीय खाद्य निगम तथा सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। इस समिति के लिए क्रय एजेन्सी तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने प्रतिनिधि नामित किये जायेंगे।

स्टेट पूल में गेहूँ की डिलीवरी की दशा में खाद्य विभाग एवं सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। इस समिति के लिए क्रय एजेन्सी तथा खाद्य विभाग द्वारा अपने प्रतिनिधि नामित किये जायेंगे।

(2) यदि विवाद इस समिति द्वारा हल नहीं हो पाता है, तब उच्चतर समिति विवाद का निपटारा करेगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

(अ) भारतीय खाद्य निगम के सहायक प्रबन्धक।
(ब) सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के जनपद स्तरीय अधिकारी।
(स) उप संभागीय विपणन अधिकारी।

20. <u>खाद्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना</u>

राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल देहरादून स्थित कार्यालय में खोला जायेगा। नियंत्रण कक्ष का नम्बर 2740778 तथा फैक्स संख्या 2740778 होगा। नियंत्रण कक्ष प्रातः 8 बजे से सांय 8 बजे तक खुला रहेगा। इसी प्रकार संभाग स्तर पर खरीद नियंत्रण कक्ष संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में तथा जनपद स्तर पर जिलापूर्ति अधिकारियों के कार्यालयों में स्थापित किये जायेंगे। संभाग स्तर एवं जनपद स्तर से दैनिक रूप से नियमित गेहूँ खरीद से संबंधित सूचना परिशिष्ट-4 पर आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल के कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष को प्रेषित की जायेगी। गेहूँ से संबंधित

एजेन्सीवार तथा जनपदवार सूचनायें **परिशिष्ट–4** के प्रपत्र में प्रभारी नियंत्रण कक्ष द्वारा अपर आयुक्त/आयुक्त को प्रतिदिन प्रस्तुत की जायेगी, तथा अपर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति द्वारा रेडियोग्राम/फैक्स के माध्यम से शासन/भारत सरकार को प्रेषित की जाया करेंगी।

21. गेहूँ कय कार्य का अनुश्रवण

(1) जिला स्तर पर जिलाधिकारी/जिला खरीद अधिकारी द्वारा कय एजेन्सी एवं भारतीय खाद्य निगम के साथ सप्ताह में कम से कम एक बार अथवा आवश्यकतानुसार एक से अधिक बार बैठक कर समीक्षा की जायेगी तथा खरीद एवं सम्प्रदान कार्य में उत्पन्न कठिनाईयों का निराकरण एवं समाधान कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) सम्भाग स्तर पर संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा बोरों की व्यवस्था, गेहूँ खरीद तथा भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान आदि कार्यों की नियमित समीक्षा की जायेगी। संभागीय खाद्य नियंत्रक तथा कय एजेन्सियों के अधिकारी नियमित रूप से भारतीय खाद्य निगम के साथ बैठक करेंगे और गेहूँ खरीद कार्य की समीक्षा करेंगे तथा शासन को नियमित रूप से प्रगति एवं समस्याओं से अवगत कराते रहेंगे।

(3) उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ द्वारा संचालित किये जाने वाले कय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद एवं सम्प्रदान कार्य की समीक्षा एवं अनुश्रवण निबन्धक उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ, अपर निबन्धक उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ तथा संबंधित सहायक निबन्धक द्वारा किया जायेगा। निबन्धक, उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ विभिन्न स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व (गेहूँ खरीद योजना के कियान्वयन के संबंध में) निर्धारित कर परिपत्र जारी करेंगे तथा उसी प्रति सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध करायेगें।

22. कय केन्द्रों का निरीक्षण

(1) रबी विपणन वर्ष सत्र 2005–06 में स्थापित कय केन्द्रों का सघन एवं आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, सम्भागीय विपणन अधिकारी, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, सम्बन्धित जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा गेहूँ खरीद केन्द्रों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कय केन्द्र समय से खुलते हैं, उन पर अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध है, किसानों से नियमानुसार गेहूँ खरीद की जा रही है और किसानों को नियमित भुगतान हो रहा है तथा खरीद प्रकिया में बिचौलिये कार्यरत नहीं है। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण के समय देखी जाने वाली मुख्य बातें **परिशिष्ट–5** पर संलग्न की जा रही है, जिनकों निरीक्षण के दौरान देखकर वस्तुस्थिति का टिप्पणी में उल्लेख किया जायेगा।

(2) निरीक्षण कार्य, पी0ओ0एल0 एवं गाडी अनुरक्षण आदि पर व्यय संबंधित विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से वहन किया जायेगा। खाद्य विभाग के अधिकारियों को उपरोक्त मदों से रबी कय योजना 2005–06 में लेखाशीर्षक "4408" में धनराशि का आवंटन पृथक से किया जायेगा।

विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत गेहू खरीद व्यवस्था के सम्बन्ध में भारत सरकार के साथ MOU हस्ताक्षरित हो जाने की प्रत्याशा में उपरोक्त गेहू खरीद नीति जारी की जा रही है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुसार रबी कय योजना 2005–06 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद की प्रभावी व्यवस्था की जाये।

भवदीय,

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव।

संख्या 501 (1)/गेहूँ-खरीद/2005-06 तद्‌दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
3. सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तरांचल शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढवाल।
5. आयुक्त, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
6. संयुक्त सचिव,उपभोक्ता मामले,खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण विभाग ,कृषि भवन,नई दिल्ली।
7. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
8. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तरांचल देहरादून।
9. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
10. आयुक्त, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
11. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तरांचल देहरादून।
12. जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम देहरादून एवं हल्द्वानी।
13. निबन्धक, सहकारिता, उत्तरांचल देहरादून।
14. सम्भागीय लेखाधिकारी, खाद्य कुमायूँ एवं गढवाल सम्भाग।
15. सम्भागीय लेखाधिकारी, खाद्य कुमायूँ एवं गढवाल सम्भाग।
16. समस्त उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, उत्तरांचल।
17. सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तरांचल देहरादून।
18. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव।

23.3.05

परिशिष्ठ–1

गेहूँ खरीद वर्ष 2003–04 में व्यवस्था हेतु समय सारणी।

क0सं0	अपेक्षित कार्य	अनुमानित अवधि	अन्तिम तिथि	अधिकारी / विभाग जिसे कार्यवाही करनी है।
1	2	3	4	5
1.	प्रभारी अधिकारी गेहूँ की नियुक्ति		8–4–2005	जिलाधिकारी कय एजेंसियों द्वारा
2	कय केन्द्रों की चयन		8–4–2005	
3	कय केन्द्रों के स्थानों व एजेंसियों को अन्तिम रूप देना		8–4–2005	जिलाधिकारी
4	कय केन्द्रों की आवश्यकताओं का जिलेवार आंकलन जैसे धन, बोरे स्टाक आदि		8–4–2005	प्रभारी अधिकारी गेहूँ कय एजेंसी
5	ट्रांसपोर्ट दरों का निर्धारण		8–4–2005	जिलाधिकारी
6	मूवमैंट प्लान कय केन्द्रों से गोदामों तक		8–4–2005	भारतीय खाद्य निगम / संभागीय खाद्य नियंत्रक
7	हैण्डलिंग व ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों की नियुक्ति		8–4–2005	कय एजेंसी
8	कय केन्द्रों पर व्यवस्थायें :– (क) धन (ख) भुगतान की प्रक्रिया (ग) बोरों की व्यवस्था (घ) स्टाफ (ड) अन्य सुविधायें (च) पल्लेदार / ट्रांसपोर्ट		9–4–2005	कय एजेंसी कय एजेंसी कय एजेंसी कय एजेंसी कय एजेंसी मण्डी समिति कय एजेंसी
9	डिपों पर स्टाफ की नियुक्ति		9–4–2005	भारतीय खाद्य निगम / संभागीय खाद्य नियंत्रक
10.	कय केन्द्रों का क्रियान्वयन		10 अप्रैल से।	कय एजेंसी

परिशिष्ट–4

मूल्य समर्थन येाजना के अन्तर्गत दिनांक .....तक का विवरण

(आकंडे मी0टन में)

अ–

कमांक	कय संस्था का नाम	प्रगतिशील खरीद	प्रगतिशील डिलीवरी (मी0टन में)		
			स्टेटपूल	भा0खा0नि0(सेन्ट्रल)	योग
1	2	3	4	5	6
1	खाद्य विभाग (विपणन शाखा)				
2	सहकारिता विभाग,उत्तरांचल				
3	भारतीय खाद्य निगम				
4	उत्तरांचल एग्रो इकाई				
	कुल योग				

ब– गेहूँ की प्रगतिशील आवक.....

स– प्रचलित बाजार दर..(प्रति कुन्टल)..... .....1. न्यूनतम

2. अधिकतम

जिला खरीद अधिकारी

जनपद.....

रबी योजनान्तर्गत 2005–06 में कुमायूँ/गढ़वाल सम्भाग में विभिन्न एजेंसियों द्वारा क्रय किये गये गेहूँ का संचरण

(मात्रा मी०टन में)

क्र0 सं0	सम्भाग का नाम	क्रय संस्था का नाम	विकासखण्ड का नाम	केन्द्रों की वार्षिक आवश्यकता	विकास खण्ड से सम्बद्ध प्राप्ति केन्द्र	प्राप्ति केन्द्र से सम्बन्ध जनप
1	गढ़वाल सम्भाग	U.C.M.F, खाद्य विभाग एवँ एग्रो इकाई	जसपुर/काशीपुर/ बाजपुर/विकासनगर/ कोटद्वार	4627.00	विकासनगर SWC	देहरादून/टिहरी/ उत्तरकाशी
				3153-00	देहरादून CWC/ विभागीय	देहरादून/टिहरी गढवाल
				3173.00	कोटद्वार SWC	पौडी गढ़वाल
		तदैव	बाजपुर/रूद्रपुर/काशीपुर/गदरपुर	9097.00	ऋषिकेश विभागीय	पौडी/टिहरी गढवाल/उत्तरकाशी/देह
				4280-00	श्रीनगर CWC वाया ऋषिकेश	रूद्रप्रयाग/चमोली
			बाजपुर/रूद्रपुर/ बहादराबाद	3173.00	ज्वालापुर SWC/विभागीय	बहादराबाद/ज्वलापुर
		तदैव	गदरपुर/काशीपुर/लक्सर/रूडकी/ भगवानपुर/नारसन/खानपुर	12450.00	रूड़की विभागीय	लक्सर/भगवानपुर/रूड़की/ मंगलौर
2	कुमॉयू सम्भाग	तदैव	टनकपुर/खटीमा/नानकमत्ता क्षेत्र/सितारगंज	16772-00	टनकपुर विभागीय	पिथौरागढ/चम्पावत/टनकपुर
		तदैव	खटीमा/सितारगंज/नानकमत्ता	1100-00	खटीमा CWC	पिथौरागढ/चम्पावत/खटीमा/नानकमत
		तदैव	सितारगंज/किच्छा	1362-00	सितारगंज SWC	पिथौरागढ/चम्पावत/सितारगंज
		तदैव	किच्छा/रूद्रपुर/हल्द्वानी/कोटाबाग	5335-00	नवीनमण्डी/कमलुआगॉजा SWC	नैनीताल/चमोली/अल्मोडा /बागेश्वर
		तदैव	किच्छा/रूद्रपुर	7098-00	खत्याडी SWC	अल्मोडा/बागेश्वर
		तदैव	कोटाबाग/रामनगर/काशीपुर	4381-00	रामनगर SWC	पौडीगढवाल/रामनगर/नैनीताल/अल्मे
		तदैव	किच्छा	942-00	किच्छा SWC/विभागीय	किच्छा
		तदैव	रूद्रपुर	361-00	रूद्रपुर SWC	रूद्रपुर /गढवाल सम्भाग
		तदैव	गदरपुर	331-00	गदरपुर SWC/गूलरभोज	गदरपुर/गढवाल सम्भाग
		तदैव	बाजपुर/काशीपुर	2716-00	काशीपुर CWC/SWC	बाजपुर/काशीपुर/गढवाल
		तदैव	जसपुर	641-00	जसपुर CWC	जसपुर/गढवाल सम्भाग

(एम०सी० उप्रेती)
अपर सचिव।

MOST IMMEDIATE

No.160 (1/2004-PY.I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

...

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated the 7th December, 2004

1. The Secretary
   Food & Civil Supplies Department
   All State Governments/UT Administrations

2. Managing Director
   Food Corporation of India
   16-20, Barakhamba Lane
   New Delhi.

Subject: Price Policy for Rabi Crops of 2004-05 Season to be marketed in 2005-06 – Fixation of Minimum Support Price (MSP)

Sir/Madam,

I am directed to state that the Department of Agriculture & Cooperation, Government of India has fixed the following Minimum Support Prices for the Rabi Crops of Fair Average Quality of 2004 -05 season to be marketed in 2005-06 as under:

Commodity	Minimum Support Price (Rs. per quintal)
Wheat	640
Barley	540

Yours faithfully

(ASHESH AGARWAL)
DIRECTOR (P)
Tele.23385238

17/12/2004
अपर आयुक्त
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

Copy to: -

1. Executive Director (Commercial), FCI Hqrs, New Delhi
2. Executive Director (Procurement), FCI Hqrs, New Delhi.
3. Shri M.M. Nampoothiry, Economics & Statistical Adviser, Department of Agriculture & Cooperation, Krishi Bhavan, New Delhi.

Department of Food & Public Distribution

4. PS to Minister (CAF&PD)
5. PS to MOS (F& PD)
6. AS & FA/JS (BP&PD)/JS (Storage)
7. Director (Fin)/ Director (FCI)/Director (Movt.)/Director (PD)
8. Joint Commissioner (S&R)
9. US (PY)/ US (PY-III)/US (Fin.)
10. SO, FC (A/cs) Section
11. Control Room

Ashesh Agarwal

(ASHESH AGARWAL)
DIRECTOR (P)
Tele:23385238

No. 7-1/2005 -S&I
Government of India,
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
*****

Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated: 11th March 2005

To

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of Uttaranchal (All State Governments/UT Administration).

Sub: Uniform Specifications for Wheat and Barley for the Rabi Marketing Season 2005 – 2006.

Sir,

The Uniform Specifications decided by the Government for procurement of Wheat and Barley stocks for the Central Pool during Rabi Marketing Season 2005 – 2006 is forwarded herewith.

It is requested that the procurement of Wheat and Barley stocks by all procuring agencies be ensured strictly in accordance with these specifications. It is also requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that the farmers get due price for their produce and rejection of stocks is avoided. The farmers may also be advised to offer only dry and clean stocks. Procurement of stocks having moisture content more than 12 % and infestation be discouraged.

Receipt of this communication may please be acknowledged.

Yours faithfully,

Encl.: As above

(S. K. Srivastava)
Joint Commissioner (S&R)
Tele # 23387334.

(पी.सी. शर्मा)

---2/-

Copy to:

1. The Chairman, FCI, New Delhi.
2. The managing Director, FCI, New Delhi.
3. Executive Director (Commercial), FCI, New Delhi.
4. Manager (QC), FCI, New Delhi.
5. Manager (Marketing & Procurement), FCI, New Delhi.
6. All Zonal Managers, FCI.
7. The Managing Director, CWC, New Delhi.
8. The Secretary to the Government of India, Department of Agriculture & Cooperation, Krishi Bhawan, New Delhi.
9. Senior PPS to Secretary (F & PD)/PPS to AS & FA/JS (P & FCI)/JS (Stg.)/JS (BP & PD)/JS (Impex & EOP).
10. Director (P)/Director (FCI)/DS (PD)/Director (Finance).
11. All SGC/IGMRI/QCC offices.
12. US (BP-I)/US (BP-II)/US (Py. I, II, IV).
13. DC (S&R)/ DD (S)/ DD (TFC)/DD (SGC)/DD (QCC)/AD (Lab.)/AD (S)/AD QCC (I, II, III)/ AD (SGC).
14. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

11/3/

(B. C. Joshi)
Deputy Director (S&R)
Tele # 23384398

UNIFORM SPECIFICATION FOR INDIAN WHEAT OF ALL VARIETIES

FOR RABI MARKETING SEASON 2005 -2006

Wheat shall:

a) be the dried mature grains of Triticum vulgare, T. compactum, T. sphaerococcum, T. durum, T. aestivum and T. dicoccum.

b) have natural size, shape, colour and lustre.

c) be sweet, clean, wholesome and free from moulds, obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances including toxic weed seeds and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below.

d) be in sound merchantable condition.

e) not have any admixture of Argemone mexicana and Lathyrus sativus (khesari) in any form, colouring matter, pesticides, and any obnoxious, deleterious and toxic material.

f) Conform to PFA Rules.

Schedule showing the maximum permissible limits of different Refractions in Fair Average Quality of Wheat

Foreign Matter %	Other Food Grains %	Damaged grains %	Slightly damaged grains %	Shrivelled & Broken grains %
0.75	2.00	2.00	6.00	7.00

NOTE:

1. Moisture in excess of 12% and upto 14% will be discounted at full value. Stocks containing moisture in excess of 14% are to be rejected.

2. Within the overall limit specified for foreign matter, the poisonous weed seeds shall not exceed 0.4% of which Dhatura and Akra (Vicia species) shall not be more than 0.025% and 0.2% by weight respectively.

3. Kernels with glumes will not be treated as unsound grains during physical analysis, the glumes will be removed and treated as organic foreign matter.

...2/-

4. Within the overall limit specified for damaged grains, ergot affected grains shall not exceed 0.05%.

5. In case of stocks having living infestation, a cut at the rate of Rupee one per quintal may be charged as fumigation charges.

6. For weevilled grains determined by count, following price cuts will be imposed.

i) from the beginning of the season till end of August the rate of cut will be @ Rs. 1/- per qtl., for every 1% or part thereof.

ii) from Ist September till end of October, no cut will be imposed upto 1% while for any excess, the cut will be @ Rs. 1/- per qtl., for every 1% or part thereof.

iii) from Ist November till end of the season no cut will be imposed upto 2% while for any excess the cut will be @ Rs. 1/- per qtl., for every 1% or part thereof.

iv) stocks containing weevilled grains in excess of 3% will be rejected.

Method of Analysis

As given in Bureau of Indian Standard No. IS 4333 (Part I and II) 1967 and as amended from time to time except for weevilled grains which are to be determined by count method.

Definition of Refractions: As contained in BIS Specifications No. 2813-1995

UNIFORM SPECIFICATION FOR BARLEY FOR RABI MARKETING SEASON 2005 -2006

Barley shall:

a) be the dried mature grains of Hordeum vulgare.
b) have uniform size, shape and colour.
c) be sweet, clean, wholesome and free from moulds, obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below.
d) be in sound merchantable condition.
e) not have any admixture of Argemone mexicana and Lathyrus sativus (khesari) in any form, colouring matter, pesticide, and any obnoxious and toxic material.
f) Conform to PFA Rules.

Schedule showing maximum permissible limits of different Refractions in Fair Average Quality of Barley.

Foreign matter %	Other food grains %	Damaged grains %	Slightly damaged & touched grains %	Immature & Shrivelled grains %
0.75	5.00	3.00	8.00	8.00

N.B.

1. Within the overall limits of foreign matter, the poisonous weed seeds shall not exceed 0.5%, of which Dhatura and Akra (Vicia species) shall not be more than 0.025% and 0.2 % by weight respectively.
2. Moisture in excess of 12% and upto 14% is to be discounted at full value. Stocks containing moisture in excess of 14% are to be rejected.

...2/-

3. For weevilled grains following price cuts will be imposed:

i) from the beginning of the season till the end of August the rate of cut will be @ Rs. 1/- per qtl. for every 1% or part thereof.

ii) from Ist September till the end of October, no cut will be imposed upto 1% while for any excess , the cut will be @ Rs. 1/- per qtl. for every 1% or part thereof.

iii) from Ist November till end of the season, no cut will be imposed upto 2% while for any excess, the cut will be @ Rs.1/- per qtl. for every 1% or part thereof.

iv) stocks containing weevilled grains in excess of 3% will be rejected.

4. In case of stocks having living infestation a cut at the rate of Rs 1/- per quintal may be charged as fumigation charges.

Method of Analysis

As given in Bureau of Indian Standard No. IS 4333 (Part I & II) 1967 and as amended from time to time except for weevilled grains that are to be determined by count method.

DEFINITIONS OF REFRACTIONS: As contained in BIS Specifications No. 2813-1995